संख्या-60/1740/एक-1-2015-1(19)/2015

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
शाहजहॉपुर ।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 10 नवम्बर, 2015

विषय:- कैमुना शुगर लि0 द्वारा बिना पूर्वानुमति क्रय की गयी 12.50 एकड़ से अधिक भूमि के संक्रमण को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-प्र0स0-168/एक-1-2015-1(19)/2015, दिनॉक 01 जुलाई, 2015 को निरस्त करते हुए श्री राज्यपाल कैमुना शुगर लि0 द्वारा ग्राम दहेना तहसील जलालाबाद जिला शाहजहॉपुर में क्रय की गयी भूमि को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की धारा-154 (3) के अधीन चीनी उद्योग, कोजनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति 2013 के अन्तर्गत 10000 टी0सी0डी0 के नई चीनी मिल व को-जन की स्थापना हेतु नियत सीमा से अधिक अर्थात 12.50 एकड़ से अधिक क्रय की गई कुल भूमि 93.00 एकड़ के विनियमितीकरण हेतु अधिरोपित अर्थदण्ड रूपया 1,66,52,275/- (रूपये एक करोड़ छाछठ लाख बावन हजार दो सौ पिचहत्तर मात्र) को माफ किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) उपरोक्त संस्था द्वारा उतनी ही भूमि की अनुमति अनुमन्य होगी जो उसके लिये आवश्यक हो। आवश्यकता का निर्धारण सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के निर्धारित मानकों के अनुरूप होगी।

(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 तथा अन्य संगत शासनादेशों/नियमों के अधीन की जायेगी।

(3) संस्था द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग केवल उक्त प्रयोजन हेतु किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल निर्धारित प्रयोजन के लिये ही किया जायेगा जिसके लिये भूमि क्रय की गई है। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किये जाने पर शासन द्वारा उपर्युक्त अनुमति निरस्त कर भूमि को राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी।

shahjahanpur.up.nic.in

-2-

(5) क्रय की गई भूमि अधिकृत संस्था के नाम होगी।

(6) उक्त भूमि धारित करने हेतु किया गया प्रत्येक संक्रमण प्रचलित अधिनियमों, नियमों, विनियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अधीन होगा।

(7) संस्था के अध्यक्ष/सचिव अथवा किसी अन्य पदाधिकारी/अधिकृत पदाधिकारी द्वारा भूमि का कोई भी भाग किसी संस्था/व्यक्ति को किसी भी रूप में राजस्व विभाग की पूर्वानुमति के बिना हस्तान्तरण/विक्रय नहीं करेगा।

(8) उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर संस्था की 12.50 एकड़ से अधिक भूमि को राज्य सरकार में निहित कर लिया जायेगा तथा ऐसे निहितन के बदले कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा।

(9) उक्त संस्था के लिये ले-आउट प्लान के अनुसार भूमि अनुमन्य होगी।

(10) संस्था द्वारा क्रय/अधिग्रहीत की गयी भूमि के मध्य स्थित ग्राम सभा/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित की भूमि का पुनर्ग्रहण एवं विनिमय का प्रस्ताव अलग से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर उपर्युक्त शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-1740(1)/एक-1-2015-1(19)/2015 तद दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
4. श्री प्रदीप कुमार अस्थाना, प्रबन्ध निदेशक,कैमुना शुगर लि0 बी-3, आरोही काम्पलेक्स सेक्टर-एच, गलीगंज, लखनऊ
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)

shasnadesh.up.nic.in

विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in